मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा एवं संस्कृति विभाग में) उपमंत्री (कुमार सैलजा)

(क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जयेगी।

स्वयं सेवी संगठनों द्वारा विद्यालयों की स्थापना

2100 **श्री राम जेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(7) क्या यह सच है कि देश में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के 82.2 मिलियन बच्चे पढ़ने के लिये विद्यालय नहीं जा रहे हैं;

(ख) इस संबंध में ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिये देश में विद्यालय स्थापित करने के लिये निजी क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से एक योजना कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो स्वयंसेवी संगठनों को प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या प्रोत्साहन देने पर विचार किया जा रहा है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री कुमारी सैलजा :

(क) और (ख) मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष मुद्रित किए जाने वाले चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़ों के अनुसार 1-3-1992 को 6 से 14 आयु वर्ग की दिखाई गई जनसंख्या 15.51 करोड़ थी। इसके विपरीत, पहली से पांचवी कक्षाओं का नामांकन 30 सितम्बर, 1991 तक 10.15 करोड़ तथा छठी से आठवीं कक्षाओं का नामांकन 3.14 करोड़ था।

(ग) और (घ) स्वैच्छिक स्कूलों की योजना का मसौदा तैयार कर लिया गया है तथा उसे सभी राज्यों/एवं संघ शासित क्षेत्रों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित भी कर दिया गया है। अब तक केवल 4 राज्यों तथा 2 संघशासित क्षेत्रों के ही उत्तर प्राप्त हुए हैं। तीन राज्य/संघ शासित क्षेत्र, प्रस्तावित योजना के पक्ष में हैं तथा अन्य तीन इसके पक्ष में नहीं हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य, निम्न कार्यों के लिए स्वैच्छिक स्कूल खोलने के लिए स्वैच्छिक एजेन्सियों को सक्षम बनाना है, (क) उपेक्षित क्षेत्र एवं समूह (ख) ऐसे स्थान, जहां पारम्परिक स्कूल दुष्क्रियात्मक हो गए हैं। इन स्कूलों में छात्र मुख्यतः अनुसूचित जातियों, अनु० जनजातियों, मौसमी प्रवासी विस्थापित समुदायों के बच्चे, शहरी क्षेत्र के निर्धन बच्चे, निःसहाय बच्चे तथा सुधारालयों आदि के बच्चे होते हैं। स्वैच्छिक एजेन्सियों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाएगी। स्वैच्छिक स्कूलों की योजना की स्वीकृति मिलने पर इसे शिक्षा-विभाग द्वारा इसे प्रारम्भिक शिक्षा की सर्वव्यापकता के लिए प्रयोगात्मक तथा नवाचारी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधान की योजना के एक भाग के रूप में, कार्यान्वित किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों तथा संघशासित क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा तथा स्वैच्छिक एजेन्सियों के परियोजना प्रस्ताव, राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों के शिक्षा निदेशालयों के माध्यम से भेजा जाएगा।

Executive meeting of UNICEF

2101. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the details of requests made by your Ministry regarding Child Welfare at the latest Executive meeting of UNICEF;

(b) what was the reaction of UNICEF in this regard;

(c) whether senior officers of your Ministry visit rural areas to see for themselves the ground level implementation of UNICEF programme; and

(d) if so, details of association of Indian officials collaborating closely with UNICEF ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI BASAVARAJESHWARI) : (a) As (a) At the latest meeting of the UNICEF Executive Board, the Indian delegation made important interventions calling for renewed efforts in the spheres of nutrition, education and literacy and improvement of the status of women and involvement in family planning.

(b) The interventions were well received.

(c) Yes Sir, concerned senior officials visit rural areas to monitor the implementation of various national programme, some of which are assisted by UNICEF.

(d) Officers dealing with UNICEF assisted programmes interact with officials of the UNICEF.

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में महिला अधिकारियों के साथ भेद-भाव

2102. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में कार्यरत महिला अधिकारियों को पुरुष अधिकारियों के बराबर प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या परिवर्तन लाने का विचार रखती है, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमार सैलजा) :

(क) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित एक स्वायत्त संगठन है। सेवा संबंधी मामलों में सभी नियम और विनियम केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की भांति संस्थान के कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं। सेवा की सभी निबंधन और शर्तें जो पुरुष कर्मचारियों पर लागू होती हैं, समान रूप से संस्थान की महिला कर्मचारियों पर भी लागू होती है तथा इस संबंध में कोई भेद-भाव नहीं है।

(ख) इस संबंध में कोई कदम उठाने का विचार नहीं हैं।

मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट आफ एशियन स्टडीज

2103. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1993 में कलकत्ता में मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज की स्थापना की गई थी,

(ख) यदि हां, तो, इस संस्थान को स्थापित करने का क्या उद्देश्य था, और

(ग) इस संस्थान हेतु बनाई गई समिति में कितने सदस्य हैं और उनके क्या-क्या नाम हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी सैलजा) :

(क) जी, हां।

(ख) मुख्य उद्देश्य एशियाई अध्ययन में अनुसंधान, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान और भारत के साथ क्षेत्र के देशों के संबंधों और मौलाना अबुल कलाम आजाद के जीवन तथा कार्य पर विशेष बल देने के लिए एक केन्द्र स्थापित करना था, जिससे कि इस महान नेता की स्मृति को कायम रखा जा सके।

(ग) इस सोसायटी में 35 सदस्य हैं, जो इस प्रकार है :—

(i) पश्चिम बंगाल के राज्यपाल अध्यक्ष होंगे,

(ii) सचिव, संस्कृति विभाग भारत सरकार अथवा उनका प्रतिनिधि,

(iii) सचिव, शिक्षा विभाग भारत सरकार अथवा उनका प्रतिनिधि,

(iv) वित्त सलाहकार, संस्कृति विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि),